. AKANKSHA GARHWAL | 20|Jan|2020 |

300 marks

PART-A (paper-II)

[redacted] कौटिल्य एकेडमी
आपकी सफलता का प्रवेश द्वार .....
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED INSTITUTE
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

1 A — जन्म से लेकर 1-3 माह तक का बच्चा। शिशु कहलाता है जिसे मातृत्व देखभाल एवं स्तनपान की अतिआवश्यकता होती है।

1 B — आयुष अर्थात् आयुर्वेद, योग, आदि संबंधित जीवन प्रक्रिया, जिसे वर्तमान स्वास्थ्य प्रणाली के तहत अपनाया जाना चाहिए।

1 C — जन्म एवं मृत्यु संबंधित आकड़ों का अध्ययन एवं जनगणना प्रणाली जन्मानुपातांक कहलाती है यह जनगणना रजिस्ट्रार द्वारा नियंत्रित व तैयार किया जाता है

D — किसी व्यक्ति का अपने पद का दुरूपयोग करते हुए आय या अनुचित लाभ उठाना ही भ्रष्टाचार है। विश्व में ट्रांसपेरेंसी इन्टरनेशनल भ्रष्टाचार रोकने हेतु वैश्विक संस्था है

E — अखिल भारतीय शैक्षिक तकनीकी परिषद भारत में तकनीकि विकास व प्रशिक्षण हेतु शीर्ष संस्था है। गठन - योजना आयोग की सिफारिश पर हुआ था।

F — एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है, जो मुर्गियों, अधपका मांस के माध्यम से संचारित होती है। लक्षण - सर्दी जुकाम, तेज बुखार फेंफड़ों में संक्रमण आदि।

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

G
यूनेस्को वैश्विक स्तर पर शैक्षिक, तकनीकि, सांस्कृतिक जीवनस्तर उन्नयन हेतु शीर्ष निकाय है। भारत में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची के तहत कई स्थलों को सूचीबद्ध किया गया है

H
स्थापना - 1948 में, एक शीर्ष स्वास्थ्य संगठन है जो स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ महामारी नियंत्रण हेतु नियमावली तैयार करता है भारत में संगठन द्वारा पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया

I

J
शरीर के अंदर मौजूद एण्टीबाडी द्वारा प्रतिजन से लड़ना ही सक्रिय प्रतिरक्षण है।

K
किसी भी व्यवसाय में उत्पाद को क्रय एवं उपभोग करने वाला व्यक्ति ही उपभोक्ता कहलाता है। इसके संरक्षण हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 अधिनियमित है।

L

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

M

N

O

यह भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा व देखभाल हेतु उच्चतम संस्थान है जो भारत सरकार के नियंत्रणाधीन है। वर्तमान में लगभग (16) एम्स कार्यरत हैं जैसे - भोपाल एम्स।

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

2 B

महिला सुरक्षा सदैव ही एक अहम मुद्दा रहा है। वस्तुतः भारत में महिलाओं की सुरक्षा, कल्याणकारी जीवन एवं सम्मानपूर्वक जीवन हेतु संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं जो निम्न हैं:

1) अनुच्छेद-14 - विधि के समक्ष समानता का अधिकार
2) अनु०-15 - धर्म, लिंग, जाति, जन्म आदि आधार पर भेदभाव निषेध एवं 15(क) राज्य द्वारा संरक्षण हेतु उचित प्रयास
3) नीतिनिदेशक तत्वों के अन्तर्गत अनु० 39 - समान कार्य हेतु समान वेतन एवं 39(क) कार्य अनुसार न्याय संगत एवं प्रसूति सहायता उपबंध
4) अनु० 47 - उचित पोषाहार एवं पोषण हेतु प्रयास।

आदि तमाम प्रयासों के अलावा कई सांविधिक प्रयास भी शामिल हैं

C

यह अधिनियम मूलतः 1989 को अधिनियमित किए जाने के साथ ही प्रभाव में आया है जिसने देश के तमाम अनुसूचित जाति, जनजाति सुरक्षा एवं सम्मानपूर्वक जीवन हेतु योगदान दिया, परन्तु इसकी असफलता हेतु कई कारक जिम्मेदार हैं:

1) कई झूठे एवं निराधार आरोपों का सामने आना जिसने अधिनियम की गंभीरता को ही नकार दिया।
2) लोक अधिकारियों एवं प्रशासन के ढीले रवैये से समय अनुसार सूचना व रिपोर्ट दर्ज न होना।
3) जाति, जनजाति के लोगों के प्रति आरोपी पक्ष द्वारा भय माहौल बनाना व इस हेतु कोई नियम न होना।

निष्कर्षतः प्रशासनिक स्तर पर कठोरता आनी आवश्यक है

E

भारत में लगभग 40 मिलियन मजदूर कार्यरत है जिसमें लगभग 65.6% असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का जीडीपी में योगदान है। भारत सरकार द्वारा इसी आधार पर कई प्रावधान किए गए है :

1) पंडित दीन दयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना : 2015 से शुरू हुई योजना के तहत यूआईडी. श्रमिक कार्ड एवं स्वास्थ्य बीमा संबंधी आदि प्रावधान शामिल है।

2) मुख्यमंत्री उद्योग योजना – म.प्र. सरकार की अनुसूचित जाति जनजाति व्यक्तियों हेतु नया उद्योग शुरू करने हेतु ऋण सुविधा।

3) मुद्रा योजना, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना

निष्कर्षतः मजदूरों के कल्याण हेतु भारत में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मानकों का अनुसरण किया जाता है।

D

मध्यप्रदेश में मातृ मृत्यु दर प्रति 1000 माताओं में 173 है जबकि भारत में यह आकड़ा 130 के लगभग है। इस दर को कम करने हेतु कई प्रयास किए जा रहे हैं :

1) जननी सुरक्षा योजना – 2005 में शुरू एवं संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु माता एवं अन्य कार्यकर्ता को वित्तीय लाभ।

2) जननी शिशु सुरक्षा योजना – 2011 में शुरू, गर्भवती महिला हेतु निःशुल्क परिवहन, जाँच, पोषण आहार सुविधा।

3) मंगल दिवस योजना – 2007-08 में शुरू, गर्भावस्था देखभाल हेतु प्रत्येक मंगलवार स्वास्थ्य जानकारी प्रदान करना।

4) संजीवनी 108 – निःशुल्क एंबुलेंस सुविधा ताकि मातृत्व शिशु सुरक्षा सुनिश्चित।

निष्कर्षतः तमाम प्रयास मातृ मृत्यु दर में कमी लाने में सहायक हो

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

G

विश्व स्वास्थ्य संगठन वस्तुतः वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं संक्रामक - गैर संक्रामक रोगों से सुरक्षा हेतु शीर्षस्थ निकाय है। संगठन की भूमिका पोलियो उन्मूलन, चेचक उन्मूलन के संदर्भ में बखूबी समझी गई है परन्तु अन्य रोगो व स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यप्रणाली अपेक्षित कदमों के अनुरूप नही है। इसी संदर्भ में अमेरिका संगठन से बाहर आगया है। संगठन में कई अन्य विकसित विकासशील देशो के अनुसार कदम उठाये जाते है जैसे हाल ही में चीन प्रभाव के कारण कोरोना वायरस से लड़ने में भूमिका को कमजोर देखा गया। संगठन में कार्यप्रणाली बिना किसी दबाव के तीव्र व लक्षित होनी चाहिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन कसौटी पर नही ठहर रहा है व इसमें सुधार की गुंजाइश है।

H

निरोधात्मक कार्यक्रम से तात्पर्य, ऐसे कार्यक्रम जो रोगो से बचने हेतु पूर्व में ही अपनाए जाते है जिससे स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है। कुछ प्रमुख निरोधात्मक कार्यक्रम निम्न है।

1) सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम - 1985 में शुरू राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा। सात प्रकार के टीकों के माध्यम से प्रतिरक्षण प्रणाली मजबूत करता है।
2) मिशन इन्द्रधनुष - 2015 में शुरू बच्चों, गर्भवती महिला को टीकाकरण के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा।
3) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन - इसके तहत ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य मिशन शामिल है।
4) राष्ट्रीय पोषण मिशन - कुपोषण आदि से बचाव।

2 (a) I किसी भी व्यक्ति में संतुलित पोषक आहार की कमी या आधिक्य होना जो उसकी शारीरिक, मानसिक क्षमता को अवरुद्ध करे, कुपोषण कहलाता है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है:

(1) कम उम्र में विवाह (2) गर्भावस्था में कुपोषण
(3) शिक्षा, जागरूकता का अभाव (4) पारिवारिक पोषण

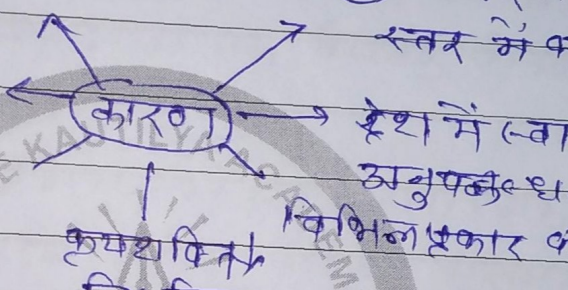

बचाव हेतु राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम, बाल संजीवनी मिशन, समन्वित बाल विकास योजना आदि कार्यक्रम संचालित।

(b) I कोविड-19 रोग कोरोना वायरस से संक्रमित एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जिसकी शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई मानी जाती है। इसके प्रसार के कारण निम्न हैं:

1) छींकने, खांसने के कारण
2) परस्पर संपर्क में रहने के कारण
3) जल, वायु संपर्क से
4) अन्तर्राष्ट्रीय आवागमन के कारण यह भारत में भी प्रसारित हुआ।

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

4

महिला स्वास्थ्य ही देश का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित कर सकता है। इस दिशा में केन्द्र व मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कई कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं:

1) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: वायु प्रदूषण से बचाव व स्वच्छ गैस उपयोग हेतु निःशुल्क गैस सिलेण्डर प्रदान।

2) जननी सुरक्षा योजना: 2005 में शुरू हुई योजना, सुरक्षित व संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु।

3) प्रोजेक्ट मुस्कान – महिलाओं में एनीमिया रोकने हेतु।

4) समन्वित बाल विकास योजना - 1976 में शुरू, महिलाओं के पोषण स्तर में वृद्धि एवं स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु।

4) किशोरी पोषण योजना आदि।

प्रश्न संख्या

Q A

किसी भी व्यक्ति के शरीर में पोषक तत्वों की कमी एवं आधिक्य के संदर्भ में शारीरिक एवं मानसिक अवरुद्धता ही कुपोषण कहलाती है। यह सामान्यतः बच्चों एवं महिलाओं से जुड़ी अहम समस्या है। वर्तमान में लगभग 14% आबादी कुपोषण से ग्रसित है। वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत उन 88 देशों में शामिल है जो 2025-30 तक वैश्विक पोषण लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ है।

मध्यप्रदेश भारत का दूसरा सर्वाधिक कुपोषित राज्य है इसी के साथ भारत वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 94 वें स्थान में सम्मिलित है। कुपोषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:

1) कम उम्र में विवाह होने से शरीर परिपक्व न हो पाना
2) लैंगिक असमानता के कारण महिलाओं में भोजन की मात्रा एवं गुणवत्ता होनों की कमी देखी जाती है।
3) क्रयशक्ति में कमी एवं निर्धनता।
4) पौष्टिक गुणवत्तायुक्त आहार एवं इसके प्रति जागरूकता की कमी।
5) पारिवारिक स्वास्थ सुरक्षा की कमी एवं अशिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी कमजोरियां।
6) अस्वच्छ वातावरण जिसमें स्वच्छ पेयजल अनुपलब्धता एवं गंदगी के तहत शारीरिक विकास की कमी।

इन तमाम कारणों से ही भारत में कुपोषण एवं परिणामस्वरूप स्वास्थ्य संबंधी समस्यायें भी उजागर हो रही है। इसे परिणामों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए:

1) भारत की जीडीपी में कुपोषण के प्रभाव से लगभग 20 से 30 प्रतिशत का नुकसान होता है

2) बच्चों एवं महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है परिणामस्वरूप अन्य रोग से ग्रसित हो जाते है।

3) स्त्रियों में रक्ताल्पता, घेंघा रोग एवं बच्चों में मरासमस, क्वाशियोरकर जैसे रोग।

4) मानसिक मंदता से देश का मानव संसाधन प्रभावित होता है

इन परिणामों के मद्देनजर ही सरकार द्वारा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कुपोषण से बचाव व निदान हेतु कई कार्यक्रम संचालित है-

- बाल संजीवनी मिशन
- राष्ट्रीय पोषण मिशन
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, 2013
- मंगल दिवस योजना
- सांझा चूल्हा कार्यक्रम
- विशेष पोषण आहार कार्यक्रम
- समन्वित बाल विकास योजना

निष्कर्षतः इन तमाम प्रयासों के साथ-
आशा कार्यकर्ता, एएनएम कार्यकर्ता भी इस समस्या
के निदान में एक अहम अंग है।

INDORE KAUTILYA ACADEMY

3 B

प्रवासी श्रमिकों से तात्पर्य एक शहर/गाँव से प्रतिस्थापन कर दूसरे शहर या कार्यक्षेत्रों में रोजगार की तलाश करना एवं इसी जीवन शैली को अपनाना।

भारत में प्रवासी श्रमिक मूलतः आंतरिक राज्यों में अधिक संख्यात्मक में मौजूद हैं जो मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ राज्यों में प्रवास करते हैं। इन श्रमिकों के आर्थिक सामाजिक जीवन अस्थिर हैं एवं सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी निम्नतम स्थिति के तहत देखा जाता है।

इसी दृष्टि से इन श्रमिकों की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं:

1) संगठित रोजगार का अभाव।
2) स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं।
3) कार्य के घंटो एवं उस आधार पर उचित वेतन में असमानता एवं अस्थायित्व।
4) आवास की समस्या एवं पारिवारिक समस्या
5) बच्चों के शैक्षिक भविष्य की समस्या।
6) सामाजिक सुरक्षा का अभाव
7)

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

3 D

मध्यप्रदेश में महिलाओं एवं बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में चिंतनीय है जहां मातृ मृत्यु दर - 173, शिशु मृत्यु दर 48 है। इसी संदर्भ में स्वास्थ्य के मानकों को हासिल करने एवं महिला बाल विकास हेतु कई कार्यक्रमों एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

1) जननी सुरक्षा योजना - 2005 में शुरू हुई योजना का उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना इस हेतु संस्थागत प्रसव करवाने पर माता एवं प्रेरित करने वाले कार्यकर्ता को वित्तीय अनुदान दिया जाता है।

2) जननी शिशु सुरक्षा योजना - 2011 में शुरू हुई योजना के तहत मध्यप्रदेश में निःशुल्क परिवहन, जाँच, औषधि युक्त भोजन की व्यवस्था गर्भवती महिला एवं बच्चे के तहत की जाएगी।

3) विजया राजे जननी कल्याण बीमा योजना - बीपीएल महिला हेतु - गर्भावस्था के दौरान वित्तीय सहायता।

4) विशेष पोषण कार्यक्रम

5) पूरक पोषण कार्यक्रम एवं संयुक्त पोषण कार्यक्रम

6) बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम

7) मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम – 1995 में शुरू हुआ कार्यक्रम शाला में उपस्थिति वृद्धि के माध्यम में बालिकाओं के पोषण स्तर को सुनिश्चित करता है।

8) <u>सबला योजना</u> – इसके तहत किशोरी बालिकाओं (11-14 वर्ष) एवं (14-18 वर्ष) के उत्तम स्वास्थ्य हेतु सरकार द्वारा उचित पोषण की व्यवस्था की जाएगी।

INDORE KAUTILYA ACADEMY

आपकी सफलता का प्रवेश द्वार .....
[redacted]र कौटिल्य एकेडमी
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED INSTITUTE
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान

PART-B

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

1 A राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माण हेतु गठित समिति, जिसने 5+3+3+4 के शैक्षिक संरचना के साथ कई पाठ्यक्रम मूल्यांकन स्तरीय प्रावधान शामिल किये है

B बच्चों में क्षयरोग से बचाव हेतु दिया जाने वाला टीका जो जन्म के प्रथम व द्वितीय सप्ताह मे दिया जाता है।

C अपनी शारीरिक, मानसिक अक्षमता के कारण पूर्णतया स्वस्थ नहीं व्यक्ति नि:शक्त कहलाते है। इन हेतु सुगम्य भारत योजना का क्रियान्वयन किया गया।

D राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत बालकों बालिकाओं के स्वास्थ्य, पोषण, शैक्षिक भविष्य हेतु नीति व कदम उठाये जा रहे है।

E किसी वित्तीय वर्ष में राजस्व प्राप्ति एवं व्यय के मध्य के अन्तर को राजकोषीय घाटा कहते है जिसमे सब्सिडी शामिल नहीं होती है।

F

INDORE KAUTILYA ACADEMY

G स्थापना - 1966, मुख्यालय - मनीला, कार्य - एशियाई देशों हेतु ऋण एवं व्यापार के सुगम मार्ग प्रदान करना - विकासात्मक परियोजना एवं फंड उपलब्ध कराना।

H वायु, जल, कीट आदि संपर्कों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने वाले रोग। उदा.- हैजा, मलेरिया, कोविड-19, एड्स, पोलियो, टायफाइड आदि।

I शरीर में आयरन की कमी से रक्तअल्पता अर्थात् एनीमिया का रोग होता है। बचाव - फोलिक एसिड गोलियां। कार्यक्रम - मध्यप्रदेश सरकार का लालिमा अभियान।

J एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। जिसमे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सभी सुविधाएं शामिल है

K मानवीय एवं प्राकृतिक कारणों से पर्यावरण एवं इसके घटकों का प्रभावित होना ही प्रदूषण है जैसे - वायु, जल, भूमि, प्रदूषण आदि।

L जनता की समस्याओं एवं कार्यों के क्रियान्वयन हेतु स्थापित केन्द्र जो समय अनुरूप कार्य संचालित करते है मध्यप्रदेश में सर्वप्रथम लोकसेवा अधिनियम 2010 पारित किया गया।

प्रश्न संख्या

मुख्य परीक्षा उत्तर पुस्तिका
(Mains Answer Sheet)

M ऐसी शिक्षा जिसमे शिक्षा की गुणवत्ता एवं मात्रा से समझौता किए बिना सभी को शैक्षिक व्यवस्था प्रदान की जाए। इसमे उम्र, योग्यता, वर्ग की अहमियत नही है

N एक भारत का उच्च तकनीकी शैक्षिक संस्थान है जो जेईई एवं गेट परीक्षा के माध्यम से संस्थान मे प्रवेश करवाता है। वर्तमान में लगभग (23) आईआईटी संस्थान संचालित है

O ऐसी मानव शक्ति जो शारीरिक मानसिक तौर पर दक्ष हो एवं देश के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करे। ऐसी मानव पूंजी ही दक्ष मानव शक्ति है

प्रश्न संख्या

2 A 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या जो देश के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करे जनांकिकीय लाभांश कहलाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा जनांकिकीय लाभांश देश है। इसके महत्व को निम्न बिन्दुओं के तहत समझा सकते हैं:

- कुशल मानव संसाधन का निर्माण एवं विकास
- देश के आर्थिक संवृद्धि में सहायक
- नवाचार एवं प्रगति के एक सूचकांक के रूप में सहायक
-

2 B व्यवसायिक शिक्षा से तात्पर्य - व्यवसाय, रोजगारोन्मुखी शिक्षा से है। भारत में व्यवसायिक शिक्षा की महत्ता अन्य देशों की तुलना में कम आंकी जाती रही है जिसके परिणामस्वरूप ही शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसकी महत्ता के चलते ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन स्तर पर दसवीं के बाद व्यवसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है।

भारत में आईटीआई, पोलिटेक्निक संस्थानों के माध्यम से व्यक्तियों को प्रशिक्षित एवं कुशल किया जाता है। व्यवसायिक शिक्षा भारत में रोजगार विविधता एवं कृषि, तकनीकि शिक्षा में निर्भरता को कम करेगी।

INDORE KAUTILYA ACADEMY

2 C कोविड-19 के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत के चलते स्कूल, कॉलेजों पूर्णतः बंद है ऐसी स्थिति में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बिना संपर्क में आये शैक्षणिक कार्य पूरे किए जा सकते हैं।

- इसके तहत तमाम ओपन वि.वि. के माध्यम से कई शैक्षणिक कार्य संपन्न किए गए।
- स्कूलों में ऑनकाइन क्लासों के माध्यम से विषयवार अध्ययन जारी रखा जा सकता है।
- कई ऑनकाइन प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब या कोई एप परीक्षा संबंधी अध्ययन पूर्ण करने में फायदेमंद साबित हो रहे हैं।

अतः दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

E प्रशासनिक सेवा कार्यपालिका का अहम अंग है जिसे अनुच्छेद 315 के तहत अखिल भारतीय स्तर पर तीन प्रकार की सेवाओं में प्राथमिक सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा है। जिसकी विशेषताएं निम्न है:

1) चयन यूपीएससी द्वारा प्रतिवर्ष परीक्षा आयोजित कर एवं राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण।
2) केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एवं केन्द्र एवं राज्य दोनों में सेवाएं देते हैं।
3) इनपर मुख्य नियंत्रण केन्द्र सरकार का होता है इससे संबंधित समस्या निदान हेतु प्रशासनिक अधिकरण का गठन।

निस्कर्षतः कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की अहम जिम्मेदारी होती है।

(...Answer Sheet)

F

G
<u>सार्क</u> अर्थात् <u>दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन</u> की स्थापना - 1985 में, मुख्यालय - काठमांडू ; <u>संगठन</u> - कुल 8 सदस्य (भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका)

<u>उद्देश्य</u> : सदस्य देशों के मध्य मुक्त व्यापार संचालन
↳ दक्षिण एशियाई क्षेत्र विकास सुनिश्चित।

<u>भविष्य</u> : वस्तुतः स्थापना विकासोन्मुखी उद्देश्य से हुई है परन्तु सदस्य देशों के <u>निजी हित टकराव</u> एवं <u>साम्राज्यवादी मंशा</u>, तुष्टीकरण नीति से संगठन की महत्ता पर चोट पहुंचती है।
• समय अनुसार <u>सम्मेलन न होना</u> व उद्देश्यों के प्रति लापरवाही से सार्क की महत्ता पर प्रश्न उठते हैं। इस दिशा में सदस्य देशों को एकजुट होकर संगठन के मूल भाव पर ध्यान दिया जाना चाहिए

[redacted] कौटिल्य एकेडमी
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED INSTITUTE
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, सर्वश्रेष्ठ संस्थान
INDORE KAUTILYA ACADEMY

F

G सार्क अर्थात् दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना -१९८५ में, मुख्यालय - काठमांडू, संगठन - कुल 8 सदस्य (भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका)

उद्देश्य : सदस्य देशों के मध्य मुक्त व्यापार संचालन
↳ दक्षिण एशियाई क्षेत्र विकास सुनिश्चित।

भविष्य : वस्तुतः स्थापना विकासोन्मुखी उद्देश्य से हुई है परन्तु सदस्य देशों के निजी हित टकराव एवं साम्राज्यवादी मंशा, तुष्टीकरण नीति से संगठन की महत्ता पर चोट पहुंचती है।
•समय अनुसार सम्मेलन न होना व उद्देश्यों के प्रति लापरवाही से सार्क की महत्ता पर प्रश्न उठते है। इस दिशा में सदस्य देशों को एकजुट होकर संगठन के मूल भाव पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

2 1

आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू (मई 2020) एक विकासोन्मुखी प्रयास है जो भारत के अहम विनिर्माण एवं उत्पादन संबंधी कार्यक्रमों को समर्थन देने के उद्देश्य से निर्मित किया गया है।

आत्मनिर्भर भारत के प्रमुख (5) स्तंभ है –

1) अर्थव्यवस्था 4) गतिशील जनसांख्यिकी
2) अवसंरचना 5) माँग
3) प्रौद्योगिकी

सरकार द्वारा महामारी के दौर में आत्मनिर्भर भारत को सहयोग देने हेतु पैकेज की भी घोषणा की है।

निष्कर्षतः इस अभियान से वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं अपितु दुनिया की मदद ही की जाएगी।

2 J

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद – भारत में कृषि संबंधी तकनीकि अनुसंधान। अनुप्रयोगों हेतु शीर्ष निकाय है। इसके योगदान की श्रृंखला निम्न है –

1) विभिन्न ट्रांसजेनिक फसलों पर अनुसंधान एवं उसके पोषणात्मक स्तर की जांच जैसे – बीटी कपास।
2) नवीन सिंचाई प्रणालियों पर शोध
3) मृदा स्वास्थ्य परीक्षण व इस दिशा में जांच

निश्चित ही परिषद कृषि विकास एवं उत्पादन प्रक्रिया में अहम योगदान देती रही है।

K

पारिवारिक स्वास्थ्य से तात्पर्य स्वास्थ्य सुनिश्चितता एवं इसी दिशा में आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। भारत में पारिवारिक स्वास्थ्य जाँच व इसमें वृद्धि हेतु राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जाता रहा है। इसी दिशा में सर्वे-4 (2015-16) के अनुसार भारत में लिंगानुपात 919 तक पहुँच गया है वही कुपोषण, बाल विवाह के स्तर में कमी देखी गई है। परन्तु शिशु मृत्यु दर के संदर्भ में जहाँ देश में कमी तो वही म०प्र० में वृद्धि संकेतित की गई है।

हाल ही में सर्वे-5 भी अपने प्रथम चरण में है। पारिवारिक स्वास्थ्य से देश व विकास का भविष्य तय किया जाता है।

L

जन्म मृत्यु समंक मूलतः जनगणना आधारित आकड़े है जो किसी देश के जन्म दर व मृत्यु दर के अलावा कई मानकों, स्तरों पर गणना करते है।

उपादेयता :- कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण मे

- स्वास्थ्य संबंधी मानकों एवं सुधारवादी कदम उठाने में आकड़ों की महत्ता
- लक्षित कार्यक्रम की दिशा में सहायक।
- वर्ग विशेष की स्पष्ट स्थिति से भविष्य में योजनाओं में भी स्पष्टता नजर आएगी
- वैश्विक स्तर पर सकारात्मक आकड़े देश की छवि को बेहतर करते है।

Q 2 A

स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है अतः इसमें सुधार करने की प्राथमिक व अहम जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। वस्तुतः स्वास्थ्य सुधार से ही देश का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

वर्तमान में जहां भारत में शिशु मृत्यु दर 34, मातृमृत्यु दर 173 है एवं 14% आबादी कुपोषण से ग्रसित है अतः स्वास्थ्य के स्तर पर प्रयास किए जाने और भी ज्यादा आवश्यक हो जाते हैं। भारत अपनी जीडीपी का लगभग 1.5 प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च करता है जो विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। अतः स्वास्थ्य सुविधा सुधार की दिशा में प्रमुख प्रयास निम्नलिखित है:

1) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017: नई नीति के तहत चिकित्सकीय प्राधिकरण, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा आदि प्रावधानों को शामिल किया गया है वही इसके प्रमुख लक्ष्य है -
- जीडीपी का 2.5% स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च
- प्रजनन दर 2.1 के स्तर पर लाना
- कुपोषण में कमी, 90:90:90 के लक्ष्य को हासिल करना। आदि।

2) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन - इसके तहत राष्ट्रीय ग्रामीण एवं शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं

- आरएमएनसीएच + ए के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा प्रसार की अभिकल्पना रखी गई है।

3) आयुष्मान भारत योजना - 2018 में शुरू 10 करोड़ परिवार के लोगों को 5 लाख तक तक स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित किया गया है।

4) प्रधानमंत्री मातृत्व सहयोग योजना - 2017 में शुरू संस्थागत प्रसव पर माता को 6000 रु की प्रोत्साहन राशि तीन चरणों के तहत प्रदान की जाएगी।

5) जननी सुरक्षा योजना - 2005 में शुरू केंद्रीय प्रायोजित योजना जिसका लक्ष्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। इसके तहत संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित करने पर गर्भवती महिला व कार्यकर्ता को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

6) जननी शिशु सुरक्षा योजना -

3 B

कौशल विकास से तात्पर्य मनुष्य की कार्य करने की शक्ति में उन्नयन। भारत में अधिकांश जनसंख्या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है एवं इसका योगदान भी जीडीपी में लगभग 65% है। इस उद्देश्य से मानव शक्ति को कौशल विकास से जोड़ना अति आवश्यक है।

इस हेतु कई नीतियों व कार्यक्रम संचालित है—

1) स्किल इंडिया कार्यक्रम – 2015 में शुरू
इसके तहत 2022 तक भारत की 70 करोड़ जनसंख्या को कौशल विकास से युक्त करना है इस हेतु समय-समय पर कई कार्यक्रम व परियोजनाएं संचालित की जाएगी।

2) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना – 2015 में शुरू
देश के अकुशल श्रमबल को प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल युक्त करना ताकि वे देश का सही तरीके से आर्थिक विकास सुनिश्चित कर सके।

3) मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कौशल प्रशिक्षण योजना – इसके तहत 18 से 35 वर्ष युवा को प्रशिक्षण दिया जाएगी।

4) शिल्पकार प्रशिक्षण योजना – 2017 में शुरू
मध्यप्रदेश सरकार की योजना जिसके तहत दसवी पास व्यक्ति को उचित क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जायेगा।

इन परियोजनाओं के लक्षित स्तर पर क्रियान्वित होते देख देश के मानव संसाधन की महत्ता व देश के विकास में भूमिका को समझा जा सकता है।

- मानव संसाधन शैक्षिक स्तरीय कार्यप्रणाली को संचालित करने में दक्ष होते है।
- यह देश के प्राकृतिक संसाधन के समुचित व उपयोगी प्रयोग की समझ से परिपूर्ण होते है।
- विनिर्माण, उत्पादन के स्तर पर नवीनता एवं अन्य देशों की तुलना में अधिक विकास सुनिश्चित कर सकते है।

निष्कर्षतः मानव संसाधन विकास की महत्ता से ही केन्द्रीय स्तर पर एक मंत्रालय का गठन किया गया है जो देश में मानव पूँजी को संसाधन बनाने का शीर्ष मंत्रालय है।

3 C सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व वर्तमान में बहुक्षेत्रीय है इसी दिशा में शिक्षा के स्तर पर इसकी महत्ता देखी जा सकती है।

वस्तुतः वर्तमान में शिक्षा दूरस्थ शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा आदि क्षेत्रों में विभक्त हो गई है जिसका सीधा संबंध सूचना प्रौद्योगिकी से है शिक्षा।

शिक्षा क्षेत्र में भूमिका :-

1) वर्तमान कोविड-19 महामारी के दौर में सभी शासकीय एवं प्राइवेट (निजी) स्कूलों में कक्षा का आयोजन ऑनलाइन (प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही हो रहा है।

2) स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति दर्ज करने हेतु एम-शाला मित्र एप के माध्यम से डिजिटल उपस्थिति की जा रही है।

3) डिजिटल बोर्ड जिसमें कंप्यूटर के माध्यम से विषयवार अध्ययन-अध्यापन कार्य किया जा रहा है।

4) स्कूलों की गतिविधियों पर नजर रखने हेतु भी सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व है।

इन तमाम बिन्दुओं के संदर्भ में उपयोगिता समझी जा सकती है परन्तु शिक्षा व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो यह प्रत्येक

फ्रेम पर प्राथमिकता रहेगी परन्तु भारत में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की कई कमियां है जो निम्न है :

1) पाठ्यक्रम एवं विषयों की राष्ट्रीय एकरूपता की कमी।

2) भाषाओं की प्राथमिकता का विषय जिसमें उत्तर एवं दक्षिण भारत में असमानता है।

3) मूल्यांकन के स्तर पर एक मानक नियमों का पालन न होना।

4) निजी स्कूलों की फीस मनमानी रवैया एवं शासकीय स्कूलों में अध्यापकों की उपस्थिति दर में गिरावट।

5) शाला छोड़ने की दर में गिरावट।

6) केवल शैक्षिक व्यवस्था होना। व्यवसायिक शिक्षा के प्रति उदासीनता।

7) शिक्षा के स्तर पर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी एवं प्रभाव देखा जाना।

8) स्कूल अवसंरचनात्मक कमी जिसमें - भवन, शौचालय, कमरे के स्तर पर अनियमितता आदि।

निष्कर्षतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन तमाम कमियों को काफी स्तर तक दूर करने की दिशा में कारगर नजर आती है इसी के साथ संगठनात्मक एवं सरकारी स्तर पर भी प्रयास किये जाने चाहिए।